भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1275

08.12.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण के लिए समुदाय संचालित पहल

1275. श्री इटेला राजेंदरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ एवं हरित शहरों एवं कस्बों का निर्माण करने के उद्देश्य से समुदाय-संचालित पहलों का ब्यौरा क्या है, ताकि नागरिकों को एकजुट होकर बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके;

(ख) क्या अभियान के तौर पर बिग एफएम ने समुद्र तटों पर बिग ईसीओ कार्निवल की मेजबानी की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और उत्साही भीड़ जुटी, जबकि अभियान के प्रयास से पर्यावरण संरक्षण के संदेश लाखों लोगों तक पहुंचे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरों/कस्बों में सड़कों के सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक शौचालयों के नवीनीकरण और भित्ति चित्र बनाने सहित भावी प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी निधि स्वीकृत और उपयोग की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों और अभियान के तहत स्वच्छ और हरित शहरों तथा कस्बों को बढ़ावा देने के लिए अनेक समुदाय-संचालित पहल शुरू की हैं। प्रमुख स्कीमों में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थल विकसित करने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई); और स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) शामिल है, जो छात्रों को पौधों के महत्व को समझने में मदद करती है और मान्यता प्राप्त पब्लिक तथा प्राईवेट स्कूलों में लागू की गई है। अब तक देश के 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 620 नगर वन स्थापित किए गए हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर 'एक पेड माँ के नाम' अभियान शुरू किया गया और देश भर में व्यापक वृक्षारोपण किया गया। यह अभियान देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अभियान में हिस्सा लेने वाले मंत्रालयों के साथ राज्य वन विभागों द्वारा मेरी लाईफ पोर्टल पर 261

करोड़ से अधिक पौधों के सफल वृक्षारोपण को दर्ज किया है, जिनमें से 45 करोड़ से अधिक पौधे शहरी क्षेत्रों में लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच), नई दिल्ली, अपने क्षेत्रीय केंद्रों के साथ एक स्वच्छ और हरित परिवेश बनाने के लिए स्वच्छता, पर्यावरणीय जागरूकता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न समुदाय-संचालित पहल का संचालन करती है। स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा के भाग के रूप में, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सहित सार्वजनिक क्षेत्रों में एनएमएनएच स्वच्छता अभियान चलाता है। जवाबदेह अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए नेचर वॉक, टॉक, फिल्म शो, पेंटिंग और स्लोगन-राइटिंग प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन अपशिष्ट पृथक्करण जैसे जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मिशन लाइफ (पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली) के तहत संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने और स्वच्छ तथा हरित शहरों और कस्बों के लिए सामूहिक नागरिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए "ग्रीन टॉक" सत्र, कार्यशालाएं और आउटरीच कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान अब तक देश भर में 03 अभियान चलाए जा रहे हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'वन नेशन, वन मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें' के स्लोगन के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले शुरू की गई एक महीने के पूर्व-अभियान कार्यकलापों के भाग के तौर पर, लगभग 69,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें देश भर में लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया। दिनांक 5 जून से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी) भी शुरू किया गया था। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के कार्यकलाप शामिल थे। इन कार्यकलापों में विशेष रूप से विशेष अभियान 5.0 के दौरान सरकारी कार्यालयों में परिहार्य एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर ध्यान देना भी शामिल था।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ युवा के साथ साझेदारी में, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 शहरों में ई-अपशिष्ट जागरूकता और न्यूनीकरण अभियान का आयोजन किया गया था, 65 आभासी कार्यशालाओं और स्कूल-आधारित संग्रह अभियानों के माध्यम से 632 सरकारी स्कूलों में 70,000 छात्रों को शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 4,950 किलोग्राम ई-अपशिष्ट का सुरक्षित पुनर्चक्रण किया गया।

मंत्रालय ने माई भारत प्लेटफॉर्म पर 10-दिवसीय अनुभवजन्य शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी) के माध्यम से मिशन लाईफ को बढ़ावा देने में युवाओं को जोड़ने की सुविधा भी प्रदान की है, जो सीखने और सामुदायिक जुड़ाव की पेशकश करता है। प्रतिभागियों ने यूनिसेफ इंडिया के कार्यालय परिसर में आयोजित मिशन लाईफ पर एक अभिविन्यास सत्र के साथ मिशन लाईफ के सात विषयों को समझने के लिए कई डू इट योरसेल्फ कार्यकलापों को पूरा किया। इसके अलावा, अब तक 6 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने 33.17 लाख लाईफ संबंधी कार्यकलापों में भाग लिया।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) भारत सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी पहल है, जो वर्ष 2017-18 में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा शुरू की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एसएपी कार्यान्वयन के दायरे में वर्तमान में स्वच्छता के संबंध में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जैव-शौचालयों का निर्माण शामिल है। एसएपी को "पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास" योजना के पर्यावरणीय सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम के तहत मुख्यधारा में लाया गया है। कार्यक्रम के दायरे में अब राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जैव-शौचालयों का निर्माण भी शामिल है ताकि आगंतुकों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित किया जा सके। एसएपी को “पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास योजना के पर्यावरणीय सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम के तहत मुख्यधारा में लाया गया है।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किसी भी समुद्री तटीय सफाई अभियान या बिग इको कार्निवल की मेजबानी बिग एफएम ने नहीं की है। हालांकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय समुदायों और समुद्र तट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों में 80 से अधिक समुद्री तटों को शामिल करके तटीय राज्य सरकारों के सहयोग से समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया है। इन अभियानों में आसपास के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों, एनसीसी और एनएससी कैडेट, तटरक्षक कर्मियों, एनजीओ/सीएसओ (सिविल सोसाइटी संगठनों) और जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। पूरे देश में कुल 13 ब्लू फ्लैग बीच चिह्नित किए गए हैं।

मंत्रालय पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बच्चों/युवाओं को संवेदनशील बनाने और कार्यशालाओं, परियोजनाओं, प्रदर्शनियों, अभियान, प्रतियोगिताओं, प्रकृति शिविरों, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रमों आदि जैसी शैक्षणिक पहलों के माध्यम से उन्हें संधारणीय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) लागू करता है। यह कार्यक्रम इको-क्लबों के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को प्रकृति और व्यावहारिक कार्यकलापों के अनुभव के साथ कक्षाओं से प्राप्त ज्ञान की सहायता करना है। इन समुद्री तटों के सफाई अभियान, अपशिष्ट-पृथक्करण प्रदर्शन, चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रणालियों पर जागरूकता सत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक कला परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यकरण, स्वच्छता और पहुंच में सुधार के लिए सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण और उन्नयन, भित्ति चित्रों की पेंटिंग, स्ट्रीट आर्ट बनाना और हरित गलियारों का निर्माण करना शामिल है।

(घ) वर्ष 2020-21 से नगर वन योजना के तहत 50784.64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और स्कूल नर्सरी योजना के लिए 7.38 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

****